

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और वाणिज्य शिक्षा का भविष्य

डॉ. चांदनी मिश्रा

अतिथि विद्वान - वाणिज्य विभाग

शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश

सारांश:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जो बहु-विषयी शिक्षा, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी एकीकरण और समावेशी दृष्टिकोण पर जोर देती है। यह नीति वाणिज्य शिक्षा के भविष्य को नया आकार देने का प्रयास करती है, जहां पारंपरिक सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक कौशलों, उद्यमिता और डिजिटल साक्षरता से जोड़ा जाता है। इस शोध पत्र में, 2023 तक के क्रियान्वयन के आधार पर एनईपी 2020 के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है, जिसमें वाणिज्य शिक्षा में बहु-विषयी पाठ्यक्रम, क्रेडिट सिस्टम, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) और व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण पर ध्यान केंद्रित है। शोध द्वितीयक स्रोतों जैसे सरकारी दस्तावेजों, शैक्षणिक पत्रिकाओं और वेब खोजों पर आधारित है। परिणाम दर्शाते हैं कि एनईपी 2020 वाणिज्य शिक्षा को अधिक रोजगार-उन्मुख बनाती है, जहां छात्रों को फिनटेक, ई-कॉमर्स और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में कौशल प्राप्त होते हैं, जिससे सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 26.3% से बढ़कर 50% तक पहुंचने का लक्ष्य है। हालांकि, क्रियान्वयन में चुनौतियां जैसे बुनियादी ढांचे की कमी, शिक्षक प्रशिक्षण की अपर्याप्तता और ग्रामीण-शहरी असमानता मौजूद हैं। 2023 तक, एसएआरटीएचएक्यू योजना के तहत 297 कार्यों की शुरुआत हुई है, लेकिन पूर्ण क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों का सहयोग आवश्यक है। यह पत्र सुझाव देता है कि एनईपी 2020 के सफल क्रियान्वयन से वाणिज्य शिक्षा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेगी, भारत को ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदल देगी। भविष्य में, वाणिज्य शिक्षा उद्योग की मांगों से जुड़कर आर्थिक विकास को गति देगी, लेकिन इसके लिए निरंतर निगरानी और संसाधन आवंटन जरूरी है।

कीवर्ड्स:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, वाणिज्य शिक्षा, बहु-विषयी दृष्टिकोण, कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा, क्रियान्वयन चुनौतियां, सकल नामांकन अनुपात, उच्च शिक्षा सुधार, उद्यमिता, डिजिटल एकीकरण, भविष्य की संभावनाएं, भारत की शिक्षा प्रणाली।

